Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

17.31 hrs.

RE: INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh): I had requested three days ago that the Industries (Development and Regulation) Amendment Bill, as passed by Rajya Sabha may be taken into consideration in the Lok Sabha. For some reasons it has not been possible to include it in the agenda so far. I would request, however, that it is an urgent measure and should be passed as early as possible. The reason is that there are certain actions tak n under this Act which are due to expire very soon, and unless this Act is amended it will be difficult to extend the period of the control and regulation. Therefore, I would request the House that as a special case, the House may kindly permit its inclusion in tomorrow's agenda so that it may be taken up for consideration tomorrow.

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): Firstly, tomorrow I think the Kerala budget will be the first thing on the agenda, and that discussion would take about two hours; definitely it will take about two hours. After that, we shall be having the Private Members' business. So, I do not think that there is any chance of this Bill being taken up tomorrow.

Mr. Speaker: But there would be three hours for Government business. . .

Shrimati Renu Chakravartty: I do not think that it will be possible for us to take it up tomorrow. If the hon. Minister likes, he can push it on for some other day. I do not know what the urgency of it is. I do not know if he cannot wait till the end. I do not know why this Bill cannot wait till the end. Otherwise, if he feels it urgent he can push it on the some other day.

Shri Bade (Khargone): The Kerala budget discussion has already begun and 40 minutes have been taken on it already. That will continue tomorrow.

Mr. Speaker: The hon. Minister says that there is some urgency in regard to this Bill.

Shrimati Renu Chakravartty: What is the urgency?

Shri T. N. Singh: As I have explained, we have taken certain concerns under our control and management under this Act. We cannot extend this control after one extension period which is expiring shortly. The existing Act only provides for one extension after the initial control period. That is due to expire on the 14th May, and there is hardly time to take this Bill up, because if this Bill is not taken up tomorrow, the budget discussion will go on and it will continue up to 7th May, and this Bill will have to wait till that time, and hence the urgency.

I would, therefore, request that the House may kindly agree to this. It is a very simple Bill, it is just an one-clause-Bill, and it may be passed in half an hour or one hour. It is almost a non-controversial Bill because it only extends the same principle which is already there.

Shrimati Renu Chakravartty: If it comes to that, we have no objection to this, but I might just tell the hon. Minister that very probably this Bill will not be able to come up tomorrow. In that case, it should come up only on the next day.

Mr. Speaker: It might be put down on the agenda, and we shall see how the business proceeds.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अभी आधे घंटे का समय और बढ़ा कर इस बिल को पास किया जा सकता है ।

17.33½ hrs.

GENERAL BUDGET (KERALA) GENERAL DISCUSSION; DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (KERALA); SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (KERALA)—*contd.*

Mr. Speaker: The House will take up the general discussion on the Budget (Kerala) for 1965-66, and also further discussion and voting on the Demands for Grants on Account in respect of the Budget (Kerala) for 1965-66 and also further discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (Kerala) for 1964-65.

श्री बड़े (खारगौन) : अध्यक्ष महोदय, केरल का बजट अपने सामने अभी आया है और केरल की सप्लीमेंटरी ग्राण्ट्स भी आई हैं । वस्तुत: यह बजट और यह ग्राण्ट्स वहां एलेक्शन होने के बाद केरल की असेम्बली में ही आनी चाहियें थीं लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि इस डिमाक्रेसी में, इस प्रजातन्त्र देश में आज इसे पालियामेंट के सामने लाकर उससे सहमति ली जाती है । इस लिये कि केरल में तीन तीन एलेक्शन होने के बाद भी वहां लेजिस्लेटिव असेम्बली की स्थापना नहीं हो सकी है और उसके सामने यह डिमाण्ड न आकर के पालियामेंट के सामने आ रही हैं ।

17.35 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

केरल में जो एलेक्शन हुए उनके अनसार वहां पर लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट्स और राइटिस्ट कम्युनिस्ट्स दोनों मिला कर उन के पक्ष 43 सदस्य आये हैं, और उनमें से 28 जेल में हैं । चाहिये तो यह था कि उन सब को बुलाना था और बुलाने के बाद यदि लेजिस्लेटिव असेम्बली नहीं चलती तो प्रेजिडेंट का प्रोक्लेमेशन होना चाहिये था । लेकिन ऐसा न करके शायद यह सोच कर कि जो कम्युनिस्ट्स जेल में हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ने के बाद शायद कांग्रेस का राज्य वहां न चले, पता नहीं किस बुद्धि का निर्माण कांग्रेस के मन में या प्रशासन के मन में हुआ कि कल एक दम से प्रोक्लेमेशन आ गया, और वहां आर्टिकल 356 के अन्तर्गत वहां पर प्रेजिडेंट्स रूल हो गया । आज इस प्रकार से वहां पर प्रजातन्त्र की हत्या हो रही है । मैं तो समझता हूं कि यह प्रजातन्त्र की हत्या ही नहीं है, बल्कि आज तो वहां कम्युनिस्ट पार्टी अधिक संख्या में आई है, कल स्वतन्त्र पार्टी आ सकती है या जनसंघ आ सकता है, इसलिये कांग्रेस चाहती है कि वहां केवल कांग्रेसी ही राज करें । वह किसी दूसरी पार्टी को वहां पर राज नहीं करने देना चाहती। तीन तीन एलेक्शन करने के बाद आज केरल में यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, और इसे कांग्रेस ने उत्पन्न किया है । तुम्हीं ने दर्द दिया है, तुम्हीं दवा देना । कांग्रेस पार्टी ही मुस्लिम लीग को विजयी करके उनसे मिल गई थी । अभी भी मैं ऐसा समझता हूं कि केरल कांग्रेस, असन्तुष्ट कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी अगर मिल जातीं तो शायद वहां पर लेजिस्लेटिव असेम्बली हो जाती । लेकिन कामराज साहब को यह अच्छा नहीं लगा, इसलिये वहां ऐसा नहीं किया गया ।

दूसरी बात यह है कि वस्तुत: नन्दा जी ने इतने लेट उन कम्युनिस्टों को अरेस्ट किया कि उन्होंने अपने ही भाग्य पर पत्थर मार लिया । कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को पहले ही अरेस्ट कर लेते या उसको इल्लीगल ठहरा देते तो जो बातें हो गई हैं, वह शायद न होतीं । लेकिन आज जिस तरह से काम किया जा रहा है उससे सम्पूर्ण देश में ही नहीं, आस पास के सभी देशों में, सारे जगत में हिन्दुस्तान की हंसी हो रही है कि कम्युनिस्ट पार्टी को